

IMPACT OF BRITISH COLONIALISM ON INDIAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT BETWEEN WORLD WAR II

Dr. Manoj Singh Yadav

Asst Prof, Dept of History, Kashi Naresh Govt PG College, Gyanpur, Bhadohi

दो विश्वयुद्ध के मध्य भारतीय औद्योगिक विकास पर ब्रिटिश उपनिवेशवाद का प्रभाव

डॉ० मनोज सिंह यादव

‘असिस्टेंट प्रोफेसर—इतिहास विभाग, काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
ज्ञानपुर भदोही

भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना से भारतीय हस्तकलाओं एवं ग्रामीण उद्योगों के विध्वंस से कृषि एवं उद्योगों का सदियों पुराना समन्वय छिन्न-भिन्न हो गया। 19 शताब्दी के अन्त तक बहुत से उद्योग धन्धे या तो नष्ट हो गये थे या फिर विनाश के पथ पर बढ़ते हुए अन्तिम सांसे गिन रहे थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय औद्योगिक विकास को बाधित करने के लिए भारतीय पूँजी का विभिन्न माध्यमों से षोशण किया गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के औद्योगिक एवं वाणिज्यिक विकास के लिए ऐसे साधनों का विकास किया जो ब्रिटेन के लिए लाभदायक हो। ब्रिटिश सरकार द्वारा रेलों का निर्माण एक ऐसा ही कदम था। इससे भारतीय खाद्य वस्तुएँ एवं कच्चा माल इंग्लैण्ड पहुँचाने के लिए बंदरगाहों तक आसानी से पहुँचने लगा किन्तु इससे भारतीय उद्योगों को कोई लाभ नहीं पहुँचा। इसी को स्पष्ट करते हुए डॉ० बुचानन ने लिखा है कि “रेलों के निर्माण से भारत की सामग्री संसार भर को उपलब्ध होने लगी और इससे स्पष्ट ही यूरोपवासियों को भारत के लिए उत्पादन में सहायता मिली न कि भारत को अपने लिए उत्पादन करने में समर्थ बनाने में।”

प्रथम विश्वयुद्ध के कुछ ही पहले भारतीय अर्थ व्यवस्था विशेषकर पूंजीपति उद्योगों में दिवालियापन की लहर दौड़ गई थी। इसका मुख्य कारण युद्ध के पहले देश का आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विकास था। 1905-1908 के बीच के राष्ट्रीय जन आंदोलनों ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद को कमजोर करके भारतीय पूंजी को सहायता दी थी। इससे भारतीय बुर्जआ वर्ग को लाभ हुआ। टाटा स्टील एण्ड आयरन कम्पनी ने युद्ध के दौरान लाभ कमाकर बम्बई के पूंजीपति वर्ग के सहयोग से 1911 तथा 1919 ई० में दो पावर स्टेशनों का निर्माण किया किन्तु इस प्रकार पूंजीपति वर्ग द्वारा कमाये गये लाभ का उपयोग पूंजीवाद के विकास के लिए नहीं किया गया क्योंकि उन पर औपनिवेशिक राज्यों का दबाव था। भारत के औद्योगिक विकास के प्रति ब्रिटिश नीति को स्पष्ट करते हुए बी० डी० बासु ने लिखा है कि “भारत में ब्रिटिश राजनीतिक शक्ति की शुरु से अंत तक यही नीति रही कि वह भारतीय व्यापार एवं उद्योग को निरूत्साहित करे और यह बताए कि भारतीयों में न तो व्यापार की योग्यता है और न ही प्रबंधात्मक शक्ति वे धन एकत्र करना चाहते हैं किन्तु उद्योगों में लगाना नहीं चाहते।”

प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात आर्थिक क्षेत्र में सरकार का लक्ष्य औद्योगिकीकरण हो गया जिसके लिए 1915 में इस नीति की घोषणा तत्कालीन वाइसराय लार्ड हार्डिंग द्वारा की गई। और ब्रिटिश सरकार भारत को एक औद्योगिक देश बनाने की ओर अग्रसर हो गई। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 1916 में थामस हालैण्ड की अध्यक्षता में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन किया गया जिसने 1918 ई० में अपनी रिपोर्ट दी। औद्योगिक आयोग ने इसका समर्थन किया कि केन्द्रीय सरकार भारत के औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित करे, यांत्रिक शिक्षा एवं अनुसंधान कार्य विकसित करें, औद्योगिक बैंको का निर्माण करे तथा निजी उद्योगों को जहाँ जरूरत हो प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता दे। औद्योगिक आयोग की सलाह के लिए एक वित्त आयोग का गठन किया गया। इन रिपोर्टों के फलस्वरूप 1923 में टैरिफ बोर्ड का गठन किया गया जिसने 1923-1939 के बीच 51 उद्योगों की जाँचकर 11 उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया जिसमें आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, कागज

सूती कपड़ा, दिया सलाई, नमक, भारी रासायनिक पदार्थ, जौ, गेहूँ एवं चावल के विभिन्न उत्पाद प्रमुख थे।

औद्योगिक विकास के लिए केन्द्रीय उद्योग एवं षोध व्यूरो की स्थापना की गई किन्तु ये सभी पर्याप्त नहीं थी। डॉ० विष्वसरेया ने अपनी पुस्तक च्चसंददमक म्बवदवउल व्िपदकपं में लिखा है कि “इन सब उपायों के बावजूद भारतीय उद्योगों के स्वतंत्र, त्वरित एवं भरपूर विकास की षर्ते पूर्ण नहीं हुई। भारी उद्योग आज की सबसे बडी आवश्यकता है किन्तु इसके विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया था।” भारतीयों द्वारा षुरु किये गये बैंकिंग व्यवसाय पर भी विदेशी पूँजी का प्रभाव पड़ा। 1920 के अंतिम दो वर्षों को छोड़कर मद्रास प्रेसीडेंसी बैंक का कोई भारतीय गर्वनर नहीं बनाया गया था। भारतीय उद्योगपतियों की षिकायत रहती थी कि भारतीय बैंक व्यवस्था पर ब्रिटेन के नियंत्रण का इस्तेमाल भारत के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास को नुकसान पहुँचाने के लिए किया गया है। इसके अतिरिक्त भारतीयों को इन बैंको से ऋण प्राप्त करने में भी कठिनाई होती थी जिसके कारण वे उद्योग धन्धों की स्थापना करने में स्वयं को असहाय महसूस करते थे। एम० विष्वेष्वरैया ने Planned Economy of India में लिखा है कि “भारत में उद्योग धन्धों को षुरु करने के मार्ग में जो कठिनाइयाँ हैं उनमें प्रमुख कठिनाई वित्त की है। इसका वास्तविक कारण यह है कि देश की मुद्रा षक्ति सरकार के नियंत्रण में है और वह औद्योगिक नीतियों के सम्बन्ध में भारतीय नेताओं से सहमत नहीं है। ऐसे बैंक बहुत कम हैं जिन पर भारतीय व्यापारियों का अधिकार है तथा बड़े बैंको में से अधिकतर या तो सरकारी प्रभाव में हैं या फिर उनमें विदेशी पूँजी लगी हुई है।”

द्वितीय युद्ध के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था जर्जर स्थिति में पहुँच गई थी जिसका प्रभाव औद्योगिक विकास पर भी पड़ा। द्वितीय विश्वयुद्ध के पहले जिन कम्पनियों का नियन्त्रण भारतीयों के हाथ में था उनमें वृद्धि हुई। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान सूती कपड़े के निर्यात में वृद्धि हुई। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान सूती कपड़ों के निर्यात में वृद्धि हुई जिससे नये उद्योगों की स्थापना को बल मिला।

सूती कपड़े का निर्यात

वर्ष	करोड़ गज
1938-39	19.27
1941-42	85.76
1944-45	41.53

प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उभरे व्यापारियों ने स्वयं भारत के स्वतंत्र आर्थिक विकास के लिए एक योजना बनाई जो 'बम्बई प्लान' के नाम से जानी जाती है। युद्ध के दौरान भारत पूँजीवाद में वृद्धि हुई। युद्ध के प्रारम्भिक वर्षों में भारतीय व्यापारियों ने आसाम के चाय के बागान तथा दक्षिण भारत के रबड़ एवं चाय के बागान खरीद लिये। अक्टूबर 1943 ई० में आर०पी० बदगल ने ब्रिटिश कम्पनी ई० डी० सैमसन एण्ड कम्पनी' जिसके अधिकार क्षेत्र में 6 सूती कपड़ों की मिले थी को खरीद कर उसका नाम 'अग्रवाल एण्ड कम्पनी' रख दिया। डालमिया ने भी अनेकों फैक्ट्रियों को खरीदा।

इस प्रकार स्पष्ट है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा अनेकों कठिनाइयों के उपस्थित किये जाने के बावजूद भी दोनों विश्वयुद्धों के मध्य भारत का औद्योगिक विकास हुआ किन्तु यह उतनी तेज गति से नहीं हुआ जिस गति से होना चाहिए था। मशीनों के प्रचलन से ऐसे मजदूरों की संख्या बढ़ने लगी जिन्हे कोई काम उपलब्ध नहीं हो रहा था। The Economist Indian Supplementry में भारत के औद्योगिक विकास को चिन्हित करते हुए कहा गया कि "उद्योगों पर निर्भर जनता की दिनों दिन क्षति होने लगी विशेषतया जूट एवं सूती कपड़ा उद्योगों में लगे मजदूर समाप्त हो गये। यद्यपि भारत ने अपने उद्योगों को आधुनिक रूप देना शुरू कर दिया परन्तु यह कदापि नहीं कहा जा सकता था कि भारत का औद्योगिकीकरण हो गया है।"

इस औद्योगिक विकास की खास बात यह थी कि यह क्षेत्रीय दृष्टि से असंतुलित था। देश के कुछ भागों में उद्योग विकसित अवस्था में थे जबकि कुछ भागों में इनकी

संख्या नगण्य थी। इस औद्योगिक विकास के फलस्वरूप देश में नई टेक्नॉलोजी, इंजीनियरिंग कालेजों का अनेक कम्पनियों द्वारा निर्माण किया गया। इस औद्योगिक विकास में टाटा, बिडला, डालमिया आदि का महत्वपूर्ण योगदान था।

संदर्भ ग्रन्थ:

- 1-आज का भारत : रजनी पाम दत्त
- 2-इण्टरनेशनल रिलेशनस विटविन दि टू वर्ल्ड्स वार : ई० एच० कार
- 3-वार एण्ड डिपरेषन : जे० वी० कॉन्डलाइफ
- 4-भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास : विपिन चन्द्र
- 5-भारत का वृहत् इतिहास : खण्ड III आर० सी० मजूमदार
- 6-इकॉनामिक इम्पीरियलिज्म ऑफ ब्रिटेन इन इंडिया : विपिन चन्द्र
- 7-बंगाल का आर्थिक इतिहास : एन० के० सिन्हा
- 8-आधुनिक भारत का इतिहास : जगन्नाथ प्रसाद मिश्र
- 9-ब्रिटिश कालीन भारत का इतिहास : पी०ई०राबर्ट्स
- 10-आधुनिक भारत का इतिहास : पी० एल० गौतम
- 11-इण्डिया इट्स एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड प्रोग्रेस : जॉन स्ट्रेची
- 12-आधुनिक भारत का इतिहास : एम० एस० जैन
- 13-भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास : ताराचंद्र
- 14-इकोनामिक आस्पैक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इण्डिया : विपिन चन्द्र
- 15-दि कोपरेटिव आर्गनाइजेशन इन इण्डिया : बी० जी० भटनागर
- 16-आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास : सत्यसाची भट्टाचार्या
- 17-सोशल एण्ड इकोनामिक लाइफ : के० के० दत्ता

REFERENCES

1. Aaj ka Bharat: Rajni Pal Dutt
2. International Relations between the Two World War: E. H. Kar
3. War and Depression: J. V. Kandlife
4. Bharat me Arthik Rashtrabhav ka Udbhav or Vikas: Vipin Chandra
5. Bharat ka Vrihat Itihas: Part III, R. C. Majumdar
6. Economic Imperialism of Britain in India: Vipin Chandra
7. Bengal ka Arthik Itihaas: N.K. Sinha
8. Adhunik Bharat ka Itihaas: Jagannath Prasad Mishra
9. British Kaleen Bharat ka Itihaas: P.E. Roberts
10. Adhunik Bharat ka Itihaas: P. L. Gautam
11. India: Its Administration and Progress: John Strechi
12. Adhunik Bharat ka Itihaas: M. S. Jain
13. Bhartiya Swtantra Andolan ka Itihaas: Tarachandra
14. Economic Aspect of British Rule India: Vipin Chandra
15. The Co-operative Organizations in India: B. G. Bhatnagar
16. Adhunik Bharat ka Arthik Itihaas: Satyasachi Bhattacharya
17. Social and Economic Life: K. K. Dutta